"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 21, शक 1940

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 (भाद्रपद 21, 1940)

क्रमांक-8348/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018), जो बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> हस्ता./-(चन्द्र शेखर गंगराड़े) सचिव.

### छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 16 सन् 2018)

# छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्र. 15 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

#### संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

#### धारा 6 का संशोधन.

- 2. छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982(क्र. 15 सन् 1982), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, वन विकास उपकर से संबंधित धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
  - "6. व्यावृति.-धारा 6 एवं 7 का संशोधन, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या पूर्व में किये गये किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा."

#### धारा 7 का विलोपन.

- 3. मूल अधिनियम में, धारा 7 को विलोपित किया जाये.
- धारा 10 का संशोधन.
- 4. मूल अधिनियम में, धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातु :-
  - "10. किठनाईयों को दूर करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई किठनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो किठनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यत:, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 से "माल और सेवा कर" के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य करों को समाहित करते हुए "एक कर" लागू किया गया है. "एक राष्ट्र-एक कर" की अवधारणा को सुदृढ़ करने एवं "Ease of doing business" के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों को जारी रखते हुए, वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, अन्य काष्ट तथा बांस के विक्रय पर अधिरोपित "वन विकास उपकर" को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इससे राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा एवं सुगमता होगी.

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्र. 15 सन् 1982) को संशोधित करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री (भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

#### उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 में संशोधन हेतु संबंधित धाराओं 6, 7 एवं 10 का सुसंगत उद्धरण

धारा - 6

इस भाग में :-

- (क) "वन विकास उपकर" से अभिप्रेत है धारा 7 के अधीन वन विभाग द्वारा वन-उपज के विक्रय या प्रदाय पर उद्गृहीत उपकर;
- (ख) "वन विभाग" के अंतर्गत आता है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्र. 1) के अधीन गठित वन विकास निगम;
- (ग) "अभिव्यक्ति वन उपज" का यही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का क्र. 6) की धारा 2 के खण्ड (4) में दिया गया है.

धारा - 7

- (1) वन विभाग द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर उस कीमत के, जिस पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उसका प्रदाय किया जाता है, तीन प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.
- (2) उप धारा (1) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर किसी ऐसे कर के अतिरिक्त होगा जो वन-उपज पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अद्गृहणीय है.
- (3) वन विभाग द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (1) के अधीन देय वन विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसकी वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विभाग के उस अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित हो, उसी समय किया जाएगा जबकि ऐसा विक्रय या प्रदाय किया जाता है.

- (4) उपधारा (1) के अधीन उदगृहीत वन विकास उपकर के आगम प्रथमत: राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात् राज्य के संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए वन विकास उपकर के आगमों के समतुल्य हो, और उसे वन विकास निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम छत्तीसगढ़ राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय होगी.
- (5) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विवेकानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनो के लिए किया जाएगा :-
  - (क) सामाजिक वानिकी प्रयोजन,
  - (ख) वनरोपण, पुनर्वनरोपण तथा वनों का पुर्नउद्धार; और
  - (ग) वनों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें.
- (6) वन विकास निधि का संधारण और परिचालन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

#### धारा - 10

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न उद्भूत होती है तो राज्य सरकार इस कठिनाई को आदेश द्वारा, और जो इस अधिनियम में उपबंधों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी.

परन्तू ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण - इस धारा में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ होने" से, इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में, अभिप्रेत है प्रारंभ होने की वह सुसंगत तारीख जो उक्त उपबंध के संबंध में धारा (1) के अधीन नियत की गई हो.

> चन्द्र शेखर गंगराड़े सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.